

सोलदार
)
2020-21
जनता को
टोकलरी
बसो म.न.
मन्ट्री किला
रामि म.
स्थान प्रथि
0140 हे.
ला मन्तरमा
से टिकक
टोरी बैकमा
कल बैकमा
नु आगेल
बस किरी
र का उजर
निलत पेरी
रातर तिथि
अने डरा
आकलन मे
अमेरन
व आकलन
या खल्लेमा।
को यह
न्यामासय
निलर

महंगाई से गृहणियां त्रस्त हैं, पर भाजपाई अहंकार में मस्त हैं : त्रिवेदी

■ रसोई गैस के दामों में बेवजह की वृद्धि का असर 62 लाख परिवार पर पड़ेगा

रायपुर। रसोई गैस के दामों में 14 दिन के भीतर इन्हें 100 रु. प्रति सिलेंडर की वृद्धि को कांग्रेस ने मोदी निर्मित आपदा करार दिया। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि रसोई गैस के दामों में वृद्धि का कोई अंतर्राष्ट्रीय कारण नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में किसी प्रकार का बढ़ोतरी नहीं हुआ है। भारत में रसोई गैस के दामों में वृद्धि का कारण स्थानीय कंटेनर सारका की नाराजगी है। मोदी भाजपा की सरकार 14 दिन के भीतर रसोई गैस के दामों में प्रति सिलेंडर 100 रु. की वृद्धि कर देना के 62 लाख परिवार जो रसोई गैस का उपयोग करते हैं उन पर महंगाई के



बोध को बढ़ाने का काम किया है। रसोई गैस के दामों में वृद्धि के पहले खंडल-पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी किया गया था जिसका असर किसान से लेकर ट्रांसपोर्ट तक दिखाया। अगर रसोई गैस के दामों में बेवजह वृद्धि होना ही सच होता है कि मोदी सरकार ने अपने चंद मित्रों को मुनाफ़ाखोरी की खुली छूट दे रखी है। विगत 15 दिनों से देश भर में किसान आंदोलित हैं।

उनकी मांगें सुनना छोड़ आगवो की अवसर में बदलते इंधन मोदी सरकार ने 1 महीने में दूसरी बार गैस सिलेंडर के दाम में भारी

वृद्धि की है। किसानों को खान और बीज में मिलने वाली सब्सिडी पहले ही कम कर दी गयी, करोड़ों परिवारों को गैस सब्सिडी से वंचित किया गया और अब खंडल-पेट्रोल के साथ गैस सिलेंडर के दामों में भी लगातार वृद्धि कर आम जनता को लूटने का काम मोदी सरकार कर रही है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि ऐसा समय देखा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल न्यूनतम स्तर पर रहा और देश में मोदी सरकार की लूट और मुनाफ़ाखोरी सीधे रूप से किसान, गृहमयवाँ और गरीब के पेट में लाल मारने का काम कर रही है। मोदी जी नए साल से पहले और महंगा तोल्हक देने का निर्णय किया है। मोदी भाजपा की सरकार को मोदी भाजपा के आरोप लगाते हुए कांग्रेस संचार

विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि उज्जवला योजना तो बनाई है। लेकिन उज्जवला योजना के हितग्राहियों को मुफ्त दिए जा रहे रसोई गैस सिलेंडरों पर होने वाले खर्च को वहन नहीं कर रही है बल्कि उज्जवला योजना पर होने वाले खर्च को 62 लाख उपभोक्ताओं से वसूल रही है। दूसरी ओर रसोई गैस के पर 103 प्रतिशत टैक्स लगाकर रसोई गैस के दामों में वृद्धि कर रही है और रसोई गैस में मिलने वाले सब्सिडी को खर्च कर जनता के ऊपर बोझ बढ़ाने काम किया है। बीते 2 महीने में रसोई गैस में मिलने वाली सब्सिडी में 111 रु. की कटौती कर दी गई है। रसोई गैस के दामों में 14 दिन में 100 रु. की बढ़ोतरी करना मोदी भाजपा सरकार को मुनाफ़ाखोरी की नीति को दिखा रहा है।

पिता को खाना खिलाने तीन भाईयों के बीच हुआ बटवारा

■ खाना खिलाने की बात पर दो भाई परिवार सहित एक दूसरे से भिड़े

रायपुर। पिता को खाना खिलाने के बटवारा पर दो भाईयों में मारपीट होने की रिपोर्ट भारतीय थाने में दर्ज की गई है। मिर्चा जानकारी के अनुसार ग्राम भेरवा भारतीय निवासी मेहराज वर्मा 43 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज कराया है कि पिता तीन भाई हैं व मां का स्वर्णवास हो गया है। पिता काशीनाथ वर्मा को तीन भाईयों ने आपस में बटवारा कर 1-1 माह अपने पास रखकर खाना देते हैं। 15 दिसंबर को दोपहर 2 बजे प्राची के बड़े भाई ओमप्रकाश वर्मा ने पिता को खाना नहीं दिया। इसकी जानकारी होने पर पीड़ित ने पिता को खाना

दे दिया। इस पर नाराज होकर बड़ा भाई ओमप्रकाश वर्मा ने अपने बेटे फनीश वर्मा के साथ मिलकर पीड़ित को गाली-गलौचकर जान से मारने की धमकी दिया व हाथ-मुक्का एवं डंडे से मारकर उसे व बेटे लक्की वर्मा को चोट पहुंचाया। इसी तरह ग्राम भेरवा निवासी संतोषी वर्मा पति ओमप्रकाश वर्मा 48 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज कराया है कि 15 दिसंबर को देवर पोखराज वर्मा परिवारिक विवाद को लेकर प्राथमिक के पति के साथ गाली-गलौच कर अगवा कर रहा था, बीच बचाने करने जाने पर पीड़ित को पहर फेक कर मारा जिसके चलते उसके सिर पर चोट लगी है। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ अराधना कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।

रमन सिंह ने राज्य सरकार पर फिर साधा निशाना



रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने एक बार फिर भूधर सरकार के दो साल के कार्यकाल पर निशाना साधा है। डा. सिंह ने ट्वीट कर कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता दो साल में ही भूधर सरकार से उगा हुआ खसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने एक भी चाद पूरा नहीं किया है। डा. सिंह ने कहा कि देश में कौन सी ऐसी सरकार होगी जो 12 महीने में धान खरीदी के पूरे पैके तक नहीं दे सकी हो। उन्होंने कहा कि चाद खिलाने और धंधाचार इस सरकार की पहचान बन गई है।

खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के होंगे काम: मुख्य सचिव



■ मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिए निर्देश

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य शासन की प्राथमिकता की योजनाओं की प्रगति और लक्ष्य प्राप्ति के लिए विभागों की रणनीति के संबंध में राज्य के समस्त संपादायक, कलेक्टर, मुख्य वन संरक्षक, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और समस्त वनप्रणाली अधिकारियों से चर्चा की और आवश्यक मार्गदर्शन दिए। उन्होंने कहा है कि जिला खनिज विकास निधि की राशि का उपयोग प्राथमिकता से शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल-कूद के स्तर में सुधार लाने वाली गतिविधियों के

लिए किया जाना है। उन्होंने बताया है कि खनिज विकास निधि से स्वीकृत एवं पूर्ण कराए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी के लिए राज्य स्तर पर वेबपोर्टल बनाया जा रहा है। इसके लिए अगले पांच वर्षों में जिलों के द्वारा किए जाने वाले कार्ययोजना राज्य शासन को भेजने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। धान खरीदी के संदर्भ में राज्यस्य अभिलेखा (मिराजवरी) में सुधार कार्य के संबंध में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि किसानों के कचरे में सुधार का कार्य राज्यस्य अधिकारियों के भौतिक सत्यापन के बाद ही किया जाय। साथ ही उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए गिरावरी के कार्य में लापरवाही बरतने वाले उपयोग प्राथमिकता से शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल-कूद के स्तर में सुधार लाने वाली गतिविधियों के

काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नये अधिकार भी मिले हैं, नये अवसर भी मिले हैं।

किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध सरकार

- मोदी सरकार किसानों के साथ है**
- वर्ष 2013-14 में खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन रहा जो कि वर्ष 2019-20 में बढ़कर रिकार्ड वृद्धि के साथ 296.65 मिलियन टन हो गया।
 - बजट आवंटन में अमृतपूर्व वृद्धि - वर्ष 2013-14 के 21,933 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2020-21 में छ: गुना यानि 1,34,399 करोड़ रुपये का बजट दिया।
 - न्यूनतम समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक बढ़ोतरी - वर्ष 2018-19 से अधिसूचित कृषि जिलों के MSP दर में उत्पादन लागत का डेढ़ गुना निर्धारण करने की व्यवस्था।
 - किसानों के लिए एमएसपी का भुगतान - वर्ष 2019-20 में वर्ष 2013-14 की तुलना में ढाई गुना राशि से एमएसपी मूल्य पर क्रय।
 - दो चरणों में 22.57 करोड़ किसानों को मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड वितरित।
 - पीएम किसान योजना के माध्यम से किसानों के खातों में 95,979 करोड़ रुपये का हस्तांतरण तथा 10.59 करोड़ किसान परिवार लाभान्वित।
 - नीम कोटिड वृष्टिया के परिणामस्वरूप उन्नत मृदा स्वास्थ्य से बेहतर उपज मिली।
 - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - प्रति बूँद अधिक फसल - वर्ष 2015-16 में योजना के प्रारम्भ के बाद से अतिरिक्त 50.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई में कवर किया गया।
 - परम्परागत कृषि विकास योजना के तहत देश में जैविक खेती को बढ़ावा।
 - ई-नाम प्लेटफॉर्म में 1,000 बाजारों को सम्मिलित किया गया।
 - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 6.6 करोड़ आवेदक किसानों को लाभ पहुंचा।
 - संस्थागत कृषि ऋण वर्ष 2019-20 में 13.92 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो कि वर्ष 2013-14 से 6.62 लाख करोड़ रुपये अधिक है।

कृषि सुधार कानून के बारे में किसानों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है जिसकी सच्चाई यह है

MSP

एमएसपी मूल्य मिलता रहा है, मिलता रहेगा

APMC Mandi

सरकारी मंडी व्यवस्था जारी रहेगी। नये कानून मंडियों को किसानों के लिए बेहतर सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहित करेगा

किसान अब अपनी फसल कहीं भी, किसी को भी बेच सकते हैं और ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं

किसान ही अपनी जमीन के मालिक रहेंगे। कानून के तहत, जमीन की बिक्री, लीज और गिरमी सहजता प्रतिक्रियित रहेगा

किसानों के हित में सरकार और भी कदम उठा रही है

ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट से किसानों के लिए कृषि बुनियादी ढांचे के लिए 1.0 लाख करोड़ रुपये के कृषि अवरोधना कोष का प्रावधान। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सुजन होगा।

10,000 किसान उत्पादक संगठन शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से स्थापित किए जा रहे हैं। देश के हर ब्लॉक में संगठन स्थापित होगा। 6,850 करोड़ रुपये का प्रावधान।

शहद उत्पादन तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु 500 करोड़ रुपये का प्रावधान।

किसानों को समस्त सुविधाएं डिजिटली उपलब्ध कराने हेतु डिजिटल एग्री स्टैक जिसके अंतर्गत सुविधायक फार्मर्स सर्विस इंटरफेस के माध्यम से सभी किसानों को सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी।

किसान क्रेडिट कार्ड संपूर्णकरण अभियान - विगत छ: माह में कुल 1.60 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गए तथा 1,45,966 करोड़ रुपये की ऋण सीमा स्वीकृत की गई।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार

वेबसाइट : www.agricoop.nic.in किसान कॉल सेंटर 1800-1800-1551 AgriGol

स्वतंत्राधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक यशवंत थोटे* द्वारा बंसल स्कूल कैम्पस, अशोक विहार कॉलोनी, पणडरी से मुद्रित कर ब्रिस्टल चौक छोटापाड़ा रायपुर से प्रकाशित
फोन व फैक्स : 0771-4035602. RNI NO CHHHIN/2012/41806/ डाक पंजीयन क्रमांक सी जी 3/आर वार्ड पी. डीएन/40/2019-2021

रोमांस



अखिल अतिथिगन्त तहसीलदार
 हुं नगर जिला दुर्ग (छ.ग.)
व्यक्तिगत-सूचना
 ईमेल: 202011101000163

व्यक्तिगत-सूचना

[illegible]

में पिनी जाती है, जो सोसल मीडिया का कार्डे इस्तेमाल करती हैं। अक्सर वह अपने फैसन के साथ अपनी स्टाइल और बायोडिजिट सेयर करती रहती हैं। अब उन्होंने अपना ब्लैक आउटफिट में एक लैम्पर फोटो इंटरग्राफ पर शेयर किया जो न्यूयार्क शहर स्थित सिटी प्रान्सेंस को दर्शाता है, जिसका नाम 'द ग्रेट एन्डिंग' है।

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)	
--------------------------	--

सबके लिए न्याय

2 साल
बात है अभिमान के
उत्तीसगढ़िया
स्वाभिमान के

बेरोजगारी दर में कमी

बेरोजगार इंजीनियरों को
20 लाख
के कार्य ब्लाक स्तर पर
ई पंजीजन प्रक्रिया से

25 लाख
से अधिक लोगों को प्रतिदिन रोजगार
महात्मा गांधी नरेंगा के तहत

20 हजार
स्थायी शिक्षकों की भर्ती

अन्य क्षेत्रों में भी लाखों
लोगों को रोजगार

किसानों-मजदूरों को हक

18 लाख किसानों का
9000 करोड़
का कर्ज माफ़

'राजीव गांधी किसान न्याय योजना'
में किसानों के खातों में
5750 करोड़

'गोधन न्याय योजना'
सरकारी दर पर गोबर खरीदने की
योजना, प्रतिमाह औसतन भुगतान
15 करोड़

कृषि भूमि का मुआवज़ा **चार गुना**

नई स्वास्थ्य योजनाएं

डॉ खूबचंद बघेल
स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत
50 हजार से 5 लाख
तक स्वास्थ्य सहायता

मुख्यमंत्री विशेष सहायता
योजना के तहत विशेष जरूरतों पर
20 लाख तक

हर बसाहत में
स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए
मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना
मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना
दाई-दीदी क्लीनिक
डॉ राधा बाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना

बिजली बिल हाफ

21 माह में
38.42 लाख
उपभोक्ता को
1336 करोड़
की राहत

वनाश्रितों को वनाधिकार देने में देश में अग्रणी

विवरण	वनाधिकार पत्रों की संख्या	भूमि आवंटित
व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र	4.41 लाख	9.41 लाख एकड़
सामुदायिक वनाधिकार पत्र	46 हजार से ज्यादा	4.64 लाख एकड़
सामुदायिक वन संसाधन संरक्षण अधिकार पत्र	1300	5 लाख हेक्टेयर



श्री भूपेश बघेल
मानवीय मन्त्रालय, छत्तीसगढ़

